

वित्तीय बाजार के साधन एवं संरचना

नोट :- C.D.s (Certificates of Deposit) निम्न के द्वारा निकाले जा सकते हैं।

- (i) वाणिज्यिक बैंक
- (ii) आरक्षित भारतीय स्तर के वित्तीय संस्थान

इनकी अवधि न दिन से लेकर एक वर्ष तक की हो सकती है। ये भी *undiscounted* होते हैं तथा Discount पर निकाले जा सकते हैं।

नोट :- Commercial Bills व्यापारी वर्ग द्वारा निकाले जाते हैं। इनकी अवधि सामान्यतः तीन महीने की होती है। भारत में अभी यह लोकप्रिय नहीं है।

नोट :-

ट्रेजरी बिल रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं। ह्मन देने योग्य है कि राज्य सरकारें इन्हें जारी नहीं करवा सकती हैं। (UPSC PT)

इन्के माध्यम से सरकार अल्पकालिक तरलता की समस्या का समाधान करती है।

ये पूर्ण रूप से Secured होते हैं तथा discount पर निकाले जाते हैं अर्थात् ये 2010 coupon security होते हैं।

वर्तमान में भारत में निम्नलिखित प्रकार के ट्रेजरी बिल जारी किये जाते हैं-

- (i) 91-day T B
- (ii) 182-day T B
- (iii) 364-day T B

मह दमान देने योग्य है कि The RBI Retail Direct Scheme के अन्तर्गत रिटेल निवेशक (होते निवेशक सीधे T.B समेत कर प्रकार की Govt खरीद सकते हैं।

इस सन्दर्भ में इन्हे RDG (Retail Direct Govt) AIC खुलवाना पड़ता है

नोट :-

कैश मैनेजमेंट बिलान् 2010 में शुरू किए गए। ये ट्रेजरी बिल के समान होते हैं लेकिन दो मांगलों में ये उनसे अलग होते हैं

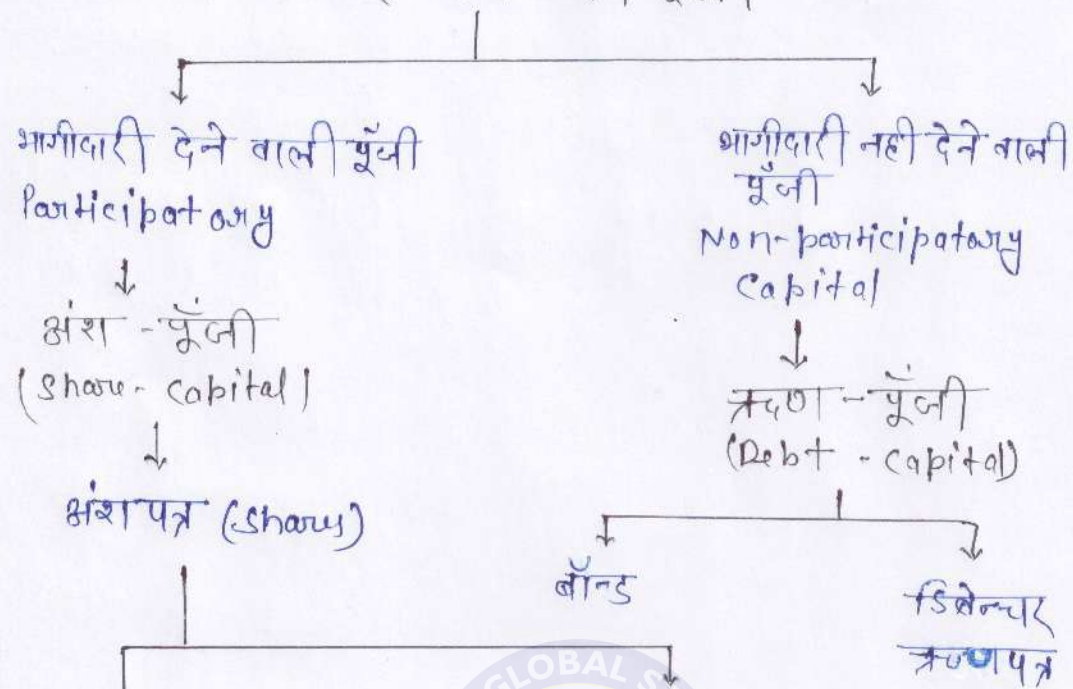
(1) इनकी अवधि 91 दिन से कम होती है।

(ii) इनकी अवधि को लेकर कोई पूर्व निर्धारित मानक नहीं है

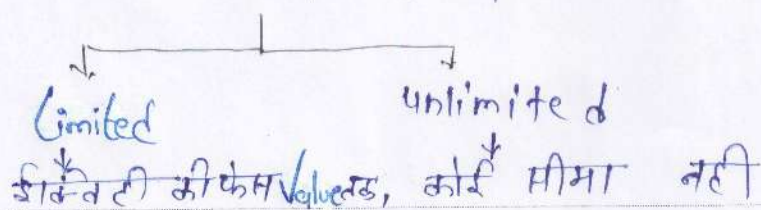
नोट - भारत में मुद्रा बाजार का नियमन रिजर्व बैंक करता है



कम्पनियों को प्राप्त होने वाली पूँजी



- (i) मुनाफे में आधिमान नहीं मिलता है।
- (ii) मुनाफे की दर निश्चित नहीं होती है।
- (iii) हानि ग्रहण नहीं करते हैं।
- (iv) देयता ग्रहण नहीं करते हैं।
- (v) देयता ग्रहण करते हैं।



(v) मताधिकार मिलते हैं

(vi) मताधिकार नहीं मिलते हैं।

भारत के शक्तिही बाजार की संरचना

